DILIP BUILDCON LIMITED
INFRASTRUCTURE & BEYOND

December 19, 2025

To
BSE Limited
Listing Department
P.J Tower, Dalal Street
Mumbai 400 001

Stock Symbol - 540047

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G
BandraKurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Stock Symbol – DBL

Sub: Newspaper Advertisement pertaining to Notice of Postal Ballot of the Company.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Business Standard (in English and Hindi) on Friday, **December 19, 2025,** regarding the Notice of Postal Ballot seeking approval of the Members.

Further, the said information is also available on the Company website at www.dilipbuildcon.com

This is for your information and records.

Yours Sincerely
For Dilip Buildcon Limited

ABHISHEK SHRIVASTAVA
Digitally signed by ABHISHEK SHRIVASTAVA
Date: 2025.12.19 14:55:50 +05'30'

Abhishek Shrivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a.a.

सेबी द्वारा फीस और ब्रोकरेज खर्च कम घटाने से

एएमसी शेयरों में आई तेजी

अभिषेक कुमार
मुंबई, 18 दिसंबर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्युचुअल फंड (एमएफ) फीस और ब्रोकरेज खर्च की सीमा में शुरुआती प्रस्ताव के मुकाबले कम कटौती की घोषणा के बाद गुरुवार को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की तेजी आई।

अक्टूबर में जारी परामर्श पत्र की तुलना में बुधवार को नियामक ने जिस संशोधित शुल्क ढांचे को मंजूरी दी, उसे दो मोर्चों पर कम सख्त माना गया- ब्रोकरेज लागत सीमा और 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति वाली इक्विटी योजनाओं द्वारा अधिकतम एक्सपेंस रेशियो।

नए एक्सपेंस रेशियो स्लैब काफी हद तक मौजूदा स्लैब जैसे ही हैं और सिर्फ स्ट्रक्चरल नजरिए से अलग हैं। ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने फंड हाउसों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे निवेशकों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क का पूरा ब्यौरा दें। टोटल एक्सपेंस रेश्यो (टीईआर) के दो मुख्य हिस्सा होंगे- बेस एक्सपेंस रेश्यो (अधिकतर फंड मैनेजमेंट फीस) और स्टैच्युअरी लेवी (एसटीटी/सीटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, सेबी फीस, एक्सचेंज फीस, वगैरह)।

सेबी ने बेस एक्सपेंस रेश्यो (बीईआर) के आधार पर नए एक्सपेंस रेशियो स्लैब जारी किए हैं। यह देखते हुए कि स्टैच्युअरी लेवी बीईआर से बाहर हैं, सभी स्लैब में सीमा को कम कर दिया गया है। शुल्क सीमा में कमी पहले प्रस्तावित योजना से कम है। पीएल कैपिटल के एक विश्लेषण के अनुसार अलग-अलग स्लैब में एक्सपेंस रेश्यो को प्रस्तावित 15 आधार अंक की तुलना में 10 आधार अंक कम कर दिया गया है।

ब्रोकरेज लागत के मामले में कैश मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए इस सीमा को 8.59 आधार अंक से घटाकर 6 आधार अंक और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए 3.89 आधार अंक से घटाकर 2 आधार अंक कर दिया गया है। कंसल्टेशन पेपर में शुल्कों को क्रमशः 5 आधार अंक और 1 आधार अंक पर सीमित करने का प्रस्ताव था।

पीएल कैपिटल ने एक रिपोर्ट में कहा, 'यह ब्रोकरों के लिए नकारात्मक होगा, लेकिन इसका असर पिछले चर्चा पत्र में बताए गए प्रस्ताव से काफी कम होगा। एक मोटे अनुमान के मुताबिक कैश ट्रांजैक्शन से राजस्व 15-20 फीसदी और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से 3-5 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकता है।'

फंड हाउसों को एग्जिट लोड वाली योजनाओं पर अतिरिक्त 5 आधार अंक वसूलने की छूट खत्म करने का प्रस्ताव बिना किसी बदलाव के मंजूर कर लिया गया।

अनुमान से कम कटौती और पिछले दो साल से शुल्क ढांचे में होने वाले बदलावों के गतिरोध को हटाने से एएमसी और उनसे जुड़े क्षेत्रों के शेयरों में तेजी आई। एचडीएफसी एएमसी को सबसे ज्यादा 7.2 फीसदी का फायदा हुआ। निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी भी 5.8 फीसदी चढ़ गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (जो शुक्रवार को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला है) में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में करीब 20 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है।

कम शुल्क कटौती से शेयर चमके

- एचडीएफसी एएमसी में 7.2 और निप्पॉन लाइफ एएमसी में 5.8 फीसदी की तेजी आई
- शुल्कों में कमी पहले के प्रस्ताव से कम है, जिससे एएमसी कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई
- सेबी ने बेस एक्सपेंस रेश्यो (बीईआर) के आधार पर नए एक्सपेंस रेशियो स्लैब जारी किए

गिरावट बरकरार, सेंसेक्स 78 अंक फिसला

स्थानीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे दिन गिरावट आई। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में नरम रुख से सेंसेक्स 78 अंक के मामूली नुकसान में रहा जबकि निफ्टी स्थिर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 77.84 अंक यानी 0.09 प्रतिशत टूटकर 84,481.81 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,780.19 अंक के ऊपरी और 84,238.43 अंक के निचले स्तर तक भी गया। इस तरह इसमें दिन के कारोबार में 541.76 अंक का उतार-चढ़ाव हुआ।

निफ्टी 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25,815.55 अंक पर स्थिर रहा। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में सन फार्मा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और भारती एयरटेल नुकसान में रहें। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अदाणी पोर्ट्स, ऐक्सिस बैंक और एचसीएल टेक शामिल हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, 'वैश्विक संकेतों और रुपये से जुड़ी चिंताओं का निवेशक धारणा पर असर बना रहा। इसकी वजह से कारोबारियों ने सतर्कता बरती।' मिडकैप सूचकांक 0.05 प्रतिशत चढ़ गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप सूचकांक में 0.28 प्रतिशत गिरावट आई। *भाषा*

सोने-चांदी की तेजी ने पैसिव एयूएम की हिस्सेदारी बढ़ाई

अभिषेक कुमार
मुंबई, 18 दिसंबर

- एयूएम में पैसिव फंडों का योगदान अब 17.4 फीसदी हो गया है। यह दिसंबर 2024 में 16.6 प्रतिशत था
- 2025 में पैसिव फंडों की वृद्धि का कारण सुस्त इक्विटी बाजार और सोने-चांदी में शानदार तेजी है

वर्ष 2024 में आई गिरावट के बाद म्युचुअल फंड (एमएफ) उद्योग में पैसिव फंडों ने फिर से बढ़त लेना शुरू कर दिया है और 2025 में कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में उनका हिस्सा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में मजबूत निवेश आने से हुई है।

फंडों की कुल एयूएम में पैसिव फंडों की भागीदारी नवंबर 2025 तक बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई जो दिसंबर 2024 के आखिर में 16.6 प्रतिशत थी। यह तेज बढ़ोतरी 2024 में आई गिरावट के बाद हुई है। तब ज्यादा जोखिम वाली सेक्रिय इक्विटी योजनाएं निवेशकों की मजबूत पसंद थीं। इस कारण इक्विटी फंडों ने बढ़त हासिल की थी। 2024 में ज्यादातर निवेश स्मॉलकैप, मिडकैप और थीमेटिक योजनाओं में हुआ था।

2025 में पैसिव फंडों का वृद्धि की पटरी पर लौटने का कारण सुस्त इक्विटी बाजार और सोने-चांदी में शानदार तेजी है। मॉर्निंगस्टार में वरिष्ठ विश्लेषक, मैनेजर रिसर्च, नेहल मेश्राम ने कहा, 'इक्विटी ईटीएफ के जरिये लगातार संस्थागत भागीदारी, साथ ही टैक्टिकल हेज के तौर पर गोल्ड ईटीएफ में बढ़ती दिलचस्पी ने पैसिव परिसंपत्तियों में वृद्धि को मजबूती प्रदान की है।'

जीरोधा फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) विशाल जैन के अनुसार सोने और चांदी के ईटीएफ में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का एक कारण कर बदलाव भी हो सकता है।

उन्होंने कहा, 'खास बात यह है कि पिछले दो साल में जोड़े गए सभी नए ईटीएफ फोलियो में से लगभग आधे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के हैं, जिसकी वजह कर में हुए फायदेमंद बदलाव हैं। दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) होल्डिंग अवधि को घटाकर एक साल कर दिया गया है और टैक्स दर को 12.5 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, जिससे विविधता और संपत्ति सृजन के लिहाज से उनका आकर्षण बढ़ा है।'

कराधान में बदलाव की घोषणा बजट 2024 में की गई थी।

सोने और चांदी के ईटीएफ के अलावा 2025 में पैसिव एयूएम ग्रोथ का श्रेय दीर्घावधि संरचनात्मक कारकों को दिया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में भारत में पैसिव फंडों को अपनाने की वजह उनकी लागत दक्षता, पारदर्शिता और नवीनतम पेशकशें रही हैं। संस्थागत प्रवाह, खासकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से, ने भी एयूएम वृद्धि में योगदान दिया है।

फंड प्रबंधकों के लिए बेंचमार्क इंडेक्स से लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के सीमित मौकों (खासकर लार्जकैप सेगमेंट में) को लेकर हो रही चर्चाओं ने भी रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाई है।

एआई-आधारित कमाई एएसके प्राइवेट वेल्थ की मुख्य थीम

बीएस संवाददाता
मुंबई, 18 दिसंबर

ब्लैकस्टोन-समर्थित एएसके ऐसेट ऐंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप की परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई एएसके प्राइवेट वेल्थ ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से होने वाले मुनाफे, व्यापार टकराव में कमी और विदेशी पूंजी निवेश की फिर से वापसी को कुछ ऐसे अहम कारणों में गिनाया है जो 2026 में बाजारों को आकार दे सकते हैं।

अपनी 'सिक्स थीम्स ऐंड वन वरी नॉट' नाम की आउटलुक 2026 रिपोर्ट में फर्म ने 6 ऐसी थीम बताई हैं जिनसे अगले साल निवेश के माहौल पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। ये हैं - एआई को अपनाना, व्यापार शुल्कों का समाधान, केंद्रीय बैंक की नीति में लचीलापन, सेक्टोरल रोटेशन, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की नए सिरे से दिलचस्पी और वैकल्पिक परिसंपत्तियों पर ध्यान बढ़ना।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा एआई चक्र पिछले टेक्नोलॉजी बूम से संरचना के हिसाब से अलग है, क्योंकि यह मूल्यांकन बढ़ने के बजाय कमाई में बढ़ोतरी से चल रहा है। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां कमाई में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं, जिससे यह बात सुनिश्चित होती है कि मौजूदा तेजी फंडामेंटलों पर आधारित है।

बदलते अमेरिका-भारत टैरिफ माहौल पर एएसके प्राइवेट वेल्थ ने कहा कि आखिर में समाधान के पक्ष में जो कारक हैं, वे जोखिम से ज्यादा हैं। टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने इसके प्रभाव का अच्छी तरह से प्रबंधन किया है, जिससे उसका कुल व्यापार संतुलन स्थिर रहा है और रुपया ऐतिहासिक दायरे में बना हुआ है।

एमसीएक्स का शेयर विभाजन 2 जनवरी को

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) ने अपने प्रस्तावित शेयर विभाजन के लिए शेयरधारकों की पात्रता के लिए शुक्रवार, 2 जनवरी की रिकॉर्ड डेट तय की है। एक्सचेंज की योजना 10 रुपये फेस वैल्यू के एक शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू के पांच शेयरों में बांटने की है। एमसीएक्स का शेयर 1.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,172 रुपये पर बंद हुआ। *बीएस*

सेबी ने छोटे मूल्य में जीरो-कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 18 दिसंबर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शर्तों में बदलाव करके जीरो-कूपन बॉन्ड को 10,000 रुपये के कम डिनॉमिनेशन में जारी करने की अनुमति दी है।

इसके तहत जारीकर्ता निजी नियोजन के जरिये जारी -अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और अपरिवर्तनीय तरजीही शेयरों (एनसीआरपीएस) की फेस वैल्यू कम कर सकते हैं।

पहले के एक सर्कुलर में सेबी ने जारी करने वालों को ऐसी प्रतिभूतियों की फेस वैल्यू घटाकर 10,000 रुपये करने की इजाजत दी थी, बशर्ते वे फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले ब्याज या लाभांश देने वाले साधन हों और उन पर कोई स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन न हो। हालांकि, इस शर्त ने जीरो-कूपन बॉन्ड को बाहर कर दिया, जो समय-समय पर ब्याज नहीं देते हैं।

बाजार कारोबारियों की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए सेबी ने माना कि जीरो-कूपन बॉन्ड (जो आमतौर पर डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और बराबर कीमत पर रिडीम किए जाते हैं) समय-समय पर मिलने वाले कूपन के बजाय कीमत में बढ़ोतरी पर रिटर्न देते हैं। नियामक ने कहा कि ये बॉन्ड समय के साथ चक्रवृद्धि रिटर्न देते हैं और पोर्टफोलियो में विविधता लाने वाले निवेशक इनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।

सेबी के खिलाफ सैट पहुंची अवधूत साठे एकेडेमी

खुशबू तिवारी
मुंबई, 18 दिसंबर

अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी (एएसटीए) ने बाजार नियामक सेबी के एक आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) में अपील की है। इस आदेश में नियामक ने 601 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को वापस करने का निर्देश दिया था और संस्थापक अवधूत साठे को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

4 दिसंबर को जारी एक आदेश में, सेबी ने आरोप लगाया था कि एएसटीए शेयर बाजार शिक्षा के नाम पर बिना पंजीकरण के निवेश परामर्श एवं शोध विश्लेषण सेवा चला रही थी।

पंचाट के रोस्टर के अनुसार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है।

बदलाव के लिए तैयार प्रतिभूति कानून

पृष्ठ 1 का शेष

यह सेबी बोर्ड के आकार का भी विस्तार करता है जिसके तहत मौजूदा 9 सदस्यों के बजाय अध्यक्ष सहित 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यह संहिता बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्णय लेने के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हितों के खुलासे को भी अनिवार्य करती है।

एसएमसी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों- स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी- को औपचारिक तौर पर मान्यता देता है। साथ ही उन्हें बिना किसी भेदभाव के पहुंच, पारदर्शिता एवं इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने और बाजार के दुरुपयोग को कम करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है। समिति संसद के अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने सबसे पहले 2021 के बजट में इस एकीकरण की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने लोक सभा में कहा, 'शुरुआती चरण में हम केवल स्थायी समिति को भेजेने के लिए विधेयक बना रहे हैं ताकि उसकी पूरी समीक्षा की जा सके। कई ऐसे मामले हैं जिन पर स्थायी समिति में व्यापक तौर पर बहस की जा सकती है। मगर उनमें से कोई भी इस विधेयक को लाने में विधायी क्षमता से संबंधित नहीं है।'

इस संहिता के तहत ऐसे कुछ उल्लंघनों को फौजदारी से बाहर करने की भी कोशिश की गई है जिनकी प्रकृति प्रक्रियात्मक अथवा तकनीकी है। ऐसे मामलों को दीवानी जुर्मानों में परिवर्तित किया गया है। मगर बाजार के दुरुपयोग जैसे उल्लंघन को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा।

रेगस्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के वरिष्ठ पार्टनर और सेबी के पूर्व अधिकारी सुमित अग्रवाल ने कहा, 'नई संहिता में समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके, लेकिन वह चीजों को अंतिम रूप देने के लिए कम है। जांच, निरीक्षण, अंतरिम आदेश और समीक्षा सभी में विस्तार की गुंजाइश है। इससे विनियमित संस्थाओं को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।'

अग्रवाल ने कहा, 'यह संहिता नियामक के विवेकाधीन और अंतरिम शक्तियों का विस्तार करती है। ऐसे में सैट अथवा अदालतों का रुख करने की गुंजाइश सीमित हो सकती है। इस संहिता की सफलता एकीकरण के तर्क पर कम और इन शक्तियों के आनुपातिक, पारदर्शी एवं संयमित प्रयोग पर अधिक निर्भर करेगी।'

वकील व्यापक देसाई ने कहा, 'विवाद के लिहाज से जुर्माने संबंधी धाराओं में बदलाव किया गया है। कुछ चीजों को काफी व्यापक और विवेकाधीन बना दिया गया है। ऐसे में अलग-अलग व्याख्या होने के कारण मुकदमेबाजी बढ़ सकती है।'

फीनिक्स मिल्स को खपत बढ़ने से मिलेगी मदद

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 18 दिसंबर

रिटेल मॉल डेवलपर द फीनिक्स मिल्स का शेयर खपत में मजबूत वृद्धि और नई संपत्तियों के मजबूत प्रस्ताव के दम पर अपने सालाना ऊंचे स्तर के पास कारोबार कर रहा है। सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए ब्रोकरों ने इस मॉल ऑपरेटर के लिए अपने आय अनुमान बढ़ा दिए थे। अक्टूबर की शुरुआत से शेयर में लगभग 14 प्रतिशत की तेजी आई है और यह अभी वित्त वर्ष 2027 के आय अनुमान के 44 गुना पर कारोबार कर रहा है।

उपभोग में मजबूत वृद्धि के कारण कंपनी ने सितंबर तिमाही में राजस्व में 22 प्रतिशत और परिचालन लाभ में 29 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। उस तिमाही में खपत में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में यह वृद्धि 12 प्रतिशत थी। यह बढ़ोतरी फीनिक्स पैलेडियम (मुंबई), फीनिक्स सिटेडल (इंदौर), पैलेडियम अहमदाबाद, फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम (पुणे) और फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया (बेंगलूरु) की वजह से हुई। फीनिक्स मार्केटसिटी बेंगलूरु और पुणे मॉल के लिए मौजूदा रीपोजशनिंग के कारण खपत सालाना आधार पर सपाट रही।

जियोजित रिसर्च ने इस शेयर को अपग्रेड किया है। उसका मानना है कि कंपनी का प्रीमियम पर लगातार फोकस, परिसंपत्ति दक्षता और अनुशासित पूंजी नियोजन से मजबूत दीर्घावधि वृद्धि और मूल्य सृजन को मदद मिलने की उम्मीद है। उसने रेटिंग को 'होल्ड' से बढ़ाकर 'खरीदें' कर दिया है और कीमत लक्ष्य संशोधित करके 1,996 रुपये कर दिया है।

फीनिक्स मिल्स के लिए सितंबर तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक और मल्टीप्लेक्स सेगमेंट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें सालाना 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फैशन में 17 प्रतिशत और उसके बाद ज्वैलरी सेगमेंट में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

नोमूरा रिसर्च ने कंपनी के पूरे हो चुकी आवासीय परियोजना में उम्मीद से बेहतर बिक्री और जीएसटी दर में बदलाव तथा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल्स में दर्ज की गई बेहतर कारोबारी गतिविधियों के कारण मौजूदा मॉलों में आगे मजबूत खपत वृद्धि की उम्मीद के चलते वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी की प्रति शेयर आय को क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने कंपनी के लिए अपने कीमत लक्ष्य को पहले के 1,350 रुपये से बढ़ाकर 1,450 रुपये कर दिया है। हालांकि, मूल्यांकन की चिंताओं, मार्जिन दबाव और खपत वृद्धि की गति को देखते हुए उसने शेयर पर 'घटाएं' रेटिंग दी है।

दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड

(सीआईएनः L45201MP2006PLC018689)
रजि. कार्यालयः प्लॉट नंबर 5, गोविंद नारायण सिंह गेट के अंदर, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)– 462016
ईमेल आईडीः db@dilipbuildcon.co.in, वेबसाइटः www.dilipbuildcon.com
दूरभाष नं. 0755–4029999, फैक्स नं. 0755–4029998

सदस्यों को सूचना

दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''कंपनी अधिनियम'' या ''अधिनियम'') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम''), विनियमन 44 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अन्य लागू प्रावधानों और सचिवीय मानकों – 2 (एसएस –2) ''सामान्य'' पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी ''बैठकें'', जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, जो समय–समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, जिसमें शामिल नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (''एमसीए परिपत्र'') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र (''सेबी परिपत्र'') (जिन्हें सामूहिक रूप से ''लागू कानून'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों से डाक मतपत्र के माध्यम से प्रस्तावों को पारित करने के लिए अनुमोदन मांग रही है जैसा कि 18 दिसंबर, 2025 (''डाक मतपत्र नोटिस'') के डाक मतपत्र नोटिस में बताया गया है। कंपनी ने गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 को पोस्टल बैलेट नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है।

कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को डाक मतपत्र नोटिस का प्रेषण केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी(ओं)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में, शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 (''कट–ऑफ डेट'') तक कंपनी/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत उनकी ई–मेल आईडी पर दिखाई देते हैं। एमसीए के परिपत्रों के माध्यम से डाक मतपत्र नोटिस और डाक मतपत्र फॉर्म की भौतिक प्रतियों को प्रसारित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे सभी व्यक्ति जो शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को कंपनी के सदस्य हैं (उन सदस्यों सहित, जिन्हें कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत न होने के कारण यह नोटिस नहीं मिला है) नोटिस में निर्दिष्ट समाधान के संबंध में वोट देने के हकदार होंगे और कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए।

लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (एमयूएफजी) द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, डाक मतपत्र नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

ई–वोटिंग की शुरुआतः	सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025
ई–वोटिंग का अंतः	शाम 5:00 बजे (आईएसटी) शनिवार, 17 जनवरी, 2026

ई–वोटिंग की प्रक्रिया/निर्देश डाक मतपत्र नोटिस में दिए गए हैं।

उक्त डाक मतपत्र नोटिस की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.dilipbuildcon.com और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (आरटीए) की वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com.पर उपलब्ध कराई जा रही है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त समय अवधि के बाद, यानी शनिवार, 17 जनवरी, 2026 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद सदस्य(सदस्यों) सेध्द्वारा प्राप्त/डाले गए कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म(फॉर्म)/इलेक्ट्रॉनिक वोट वैध/अनुमति नहीं होंगे और उनके साथ सख्ती से ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि ऐसे सदस्य(सदस्यों) से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जिन सदस्यों ने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 18 दिसंबर, 2025 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके ऐसा करें।

प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम 20 जनवरी, 2026 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करने के अलावा कंपनी की वेबसाइट (www.dilipbuildcon.com), पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड
हस्ता/–
अभिषेक श्रीवास्तव
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः भोपाल
दिनांकः 18.12.2025

No PUC, no fuel: Delhi cracks down on polluters

Bans entry of non-Delhi pvt vehicles below BS-VI standards

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 18 December

Motorists with their PUC documents at the pollution checking centre of a petrol pump, in New Delhi, on Thursday PHOTO:PTI

"No PUC, No Fuel" — that blunt message greeted motorists across Delhi on Thursday as the city, choking under dense smog, rolled out one of its most stringent enforcement drives yet to curb vehicular pollution. With the air quality index (AQI) hovering at 358, firmly in the "very poor" category, traffic police and transport department teams fanned out to city borders, toll plazas and petrol pumps, denying fuel to non-compliant vehicles and turning back non-Delhi private automobiles that failed to meet Bharat Stage VI (BS-VI) standards.

With winter tightening its grip, commuters crawled through fog-bound roads linking Delhi with Gurugram, Noida and Ghaziabad, even as authorities leaned heavily on enforcement, signalling a shift from advisory to action against a grim atmospheric backdrop.

Union Environment Minister Bhupender Yadav acknowledged that despite incremental improvements, the crisis remained unresolved. Speaking at an event, he said that while the number of days with an AQI below 200 had increased after the establishment of the Commission for Air Quality Management (CAQM), "this is not satisfactory". Nearly 40 per cent of Delhi's PM2.5 pollution, he noted, comes from vehicles. "Cities across the world that reduced pollution improved fuel quality. We moved from BS-IV to BS-VI. Old vehicles should have been phased out," Yadav said, adding that the government would "work harder and do better", with tangible results expected over the next four years.

On the ground, the message translated into queues and confrontations. At petrol pumps in central Delhi and along border stretches, officials manually checked pollution-under control (PUC) certificates and vehicle details, supported by traffic police personnel. Vehicles without valid documents were refused fuel, prompting hurried phone calls and appeals for leniency. "The rule is justified, but it's difficult when people depend on vehicles bought with their hard-earned money," said Mukesh Kumar, a motorist at a Janpath fuel station. Others backed the move, arguing that drastic steps were unavoidable.

Enforcement was visibly heavy. At the Delhi-Noida border, transport officials used electronic devices to verify BS-VI compliance. "The number of non-compliant vehicles is low today due to awareness," said sub-inspector Jitendra Kumar, adding that fines worth around ₹10,000 had been imposed since morning. At other locations, checks were entirely manual due to the absence of cameras or incomplete integration with vehicle databases.

The impact was immediate — fewer vehicles on the roads and a noticeable dip in footfall at petrol pumps. "The situation is peaceful, but customers are fewer," said Nischal Singhania, president of the Delhi Petrol Dealers' Association, urging authorities to implement the rule uniformly across the National Capital Region (NCR) to prevent motorists from refuelling in neighbouring states. Some pump owners, however, questioned the sustainability of such manpower-intensive enforcement, pointing to gaps in automatic number plate recognition systems.

Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, inspecting petrol pumps at the Gurugram border, said joint teams had been deployed to ensure strict compliance and appealed to residents to obtain PUC certificates immediately.

The drive forms part of a broader tightening under the Graded Response Action Plan (Grap). Official data underline the scale of enforcement: Action against vehicles without valid PUC certificates has more than trebled in three years, rising from 232,000 challans in 2023 to 822,000 in 2025 until December 15. Nearly 157,000 of these, each carrying a ₹10,000 fine, were issued during this year's Grap period alone. Stage IV of Grap is currently in force across the region.

City border monitoring has intensified as well. During the Grap phase, enforcement teams checked 290,000 non-destined goods vehicles, turning back 8,682, showed official data. Following CAQM directions banning diesel commercial vehicles of BS-III and below between November 1 and December 15, 3,393 such vehicles were denied entry, while hundreds more were fined within the city. The impounding of over-age vehicles has surged too, with nearly 19,500 seized in 2025 so far.

Health experts say the stakes could hardly be higher. A recent five-year study found that Delhi residents inhale particulate matter at levels up to 10 times India's safety standards and nearly 40 times World Health Organization guidelines, with pedestrians and commuters facing the greatest risk.

'We can't keep the boy like this': SC to speak to parents on euthanasia plea

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 18 December

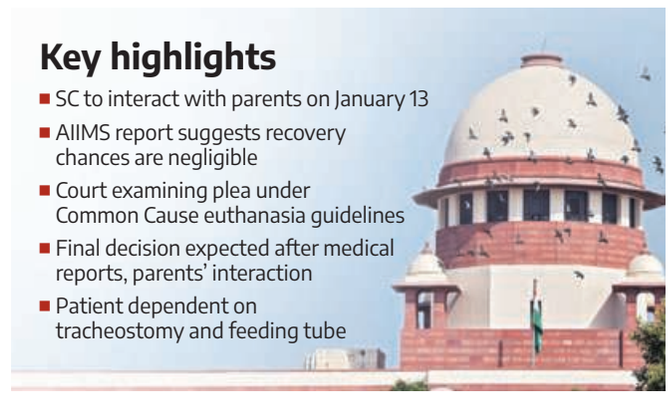

Key highlights

- SC to interact with parents on January 13
- AIIMS report suggests recovery chances are negligible
- Court examining plea under Common Cause euthanasia guidelines
- Final decision expected after medical reports, parents' interaction
- Patient dependent on tracheostomy and feeding tube

While hearing an application filed by the father of a 32-year-old man who has remained in a vegetative state for nearly 12 years after a fall from a building, the Supreme Court on Thursday said it would like to interact with the man's parents on January 13, and examine the medical report submitted by the All India Institute of Medical Sciences (Aiims).

The Bench of Justice JB Pardiwala and Justice KV Viswanathan observed that the case has reached a stage where a final decision would be required. It directed the councils to study the Aiims report in detail to assist the Court before final orders were passed.

"We have reached a stage wherein we will have to take a final call. So your thorough assistance will be required. We will ask the registry to provide you with one copy of the report. Study the report. It's a very sad report, and it will be a big challenge for us also, but we can't keep the boy like this for all time to come," the Bench said.

The report was sought in connection with the father's plea seeking permission for passive euthanasia, through the withdrawal of life-sustaining treatment. The application is being considered under the framework laid down by the Constitution Bench in Common Cause (2018), as modified by a subsequent order in January 2023, which requires opinions from multiple medical boards before passive euthanasia can be allowed.

In accordance with these guidelines, a primary medical board was earlier constituted. The board reported that the chances of recovery were negligible, noting that the patient is bedridden, dependent on a tracheostomy tube for breathing and a gastrostomy tube for feeding, and has developed extensive bed sores.

On the basis of this assessment, the Court directed that the case be examined by a Secondary Medical Board constituted by Aiims.

On Wednesday, Additional Solicitor General (ASG) Aishwarya Bhati informed the Court that the Aiims report had been submitted. After briefly perusing it, Justice Pardiwala remarked that the findings suggested the patient could not continue in his present condition indefinitely.

As copies of the report had not yet been shared with the lawyers, the court directed the Registry to provide them to Advocate Rashmi Nandakumar, appearing for the petitioner, and to the ASG.

The ASG submitted that the family would need to be consulted before any order is passed. Agreeing, the Court said it would prefer to speak to the parents in person rather than through a virtual interaction. It accordingly directed them to remain present before the bench on January 13 at 3:00 pm. in the committee room. The court also asked both councils to place their submissions in writing and directed that the Primary Medical Board's report be furnished to them.

The father had earlier approached the Supreme Court in 2024 seeking passive euthanasia for his son. At that stage, the court declined to grant the relief, though the State of Uttar Pradesh agreed to continue bearing the cost of medical treatment. The present application was filed after the father informed the Court that his son's condition had deteriorated and that he was no longer responding to treatment.

TECHDIGEST mybs.in/tech

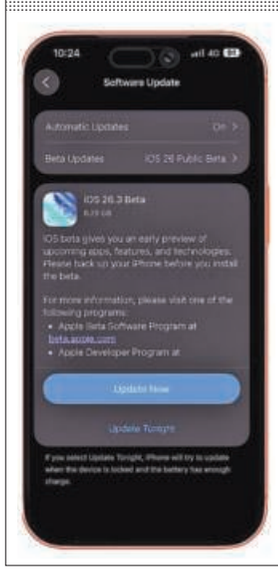

Apple release iOS 26.3 public beta

Apple has rolled out the first public beta of iOS 26.3. The update introduces new weather wallpapers, adds built-in tools to simplify data transfers when switching from an iPhone to an Android device, and brings notification forwarding support for third-party accessories.

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

Regd. & Head Office: 87, M.G. Road, Fort, Mumbai- 400 001
CIN : L66000MH1919GOI000526 , IRDAI Reg No : 190
Tel: +91 22 22708263/219/239
Email : cs.nia@newindia.co.in ; Website : www.newindia.co.in

e-TENDER FOR REQUEST FOR PROPOSAL FOR SELECTION OF REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT FOR FY 2026-27 (RTA)

(TENDER NO.: NIA/CMD_BOARD/SECTT/2025/RTA)

The New India Assurance Co. Ltd. invites online request for proposals in two bid system from SEBI registered Category I Registrar & Share Transfer Agents (RTA), having a valid registration and fulfilling eligibility criteria as stipulated in the Request for Proposal (RFP) document. The interested parties have to quote through GeM portal. The last date for submission of bids is **12th January, 2026 by 17:30 Hrs. Tenders will be accepted through online mode only.** For further details, visit our website **www.newindia.co.in** or **GeM portal.**

Date: 19th December 2025
Place: Mumbai

For The New India Assurance Co Ltd.
Sd/-
Abhishek Pagaria
Company Secretary

Hotels, villas cash in as pet parents spend more on 'paw-cations'

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 18 December

Travelling with pets in India or 'paw-cation' is moving from being a niche preference to one of the mainstream revenue drivers for the Indian hospitality sector, as Indians increasingly opt for pet-friendly bookings and accommodations. Travel operators have begun offering separate travel packages to cater to this growing segment, while hotels and alternative accommodations are adding specific inventory and services to enhance their stays. Data backs the hospitality sector's pivot to cater to their furry guests, as people spend 15-30 per cent more when travelling with pets.

Gurugram-based online travel aggregator EaseMyTrip has seen bookings linked to pets growing by 25-45 per cent each year. Pet-friendly accommodation bookings have also risen by 40-45 per cent in 2025 versus 2024. Not just domestic, but internationally too, the share of Indians flying overseas with pets has grown by 5-12 per cent in 2025 over last year, according to EaseMyTrip data. Rival player Booking.com has observed that 11 per cent of Indians are likely to take a leisure trip with pets, up from 4 per cent in 2024, as per its 2025 Travel Trends data.

"There is a clear and consistent rise in pet-inclusive travel across the country. Travellers today are far more inclined to plan holidays where their pets can be a part of the experience, a sentiment that has only strengthened post-pandemic," said Karan Agarwal, director, Cox & Kings. "Industry trends reflect this shift as pet-related bookings for flights and hotels have recorded strong year-on-year growth, with increases ranging from 15 to 18 per cent on our end to over 40 per cent across the wider ecosystem. It is a rapidly expanding segment driven by young travellers, nuclear families, and pet parents who increasingly consider their pets integral to their travel plans."

Abhishek Daga, co-founder of Thrillophilia, said that the company is piloting curated 'pet-first' road trip packages, especially drivable weekends from cities like Bengaluru, Mumbai, Pune and Delhi, where everything from the stay to open spaces, trails and cafés are chosen keeping the pet's comfort in mind. Additionally, with airline-integrated pet travel from India still being constrained by regulation and logistics, Thrillophilia is focused on surface-led, domestic pet-friendly trips in the near future.

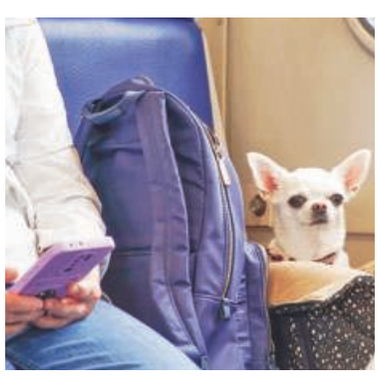

Making travel pet-friendly

- People spend 15-30 per cent more when travelling with pets

Travel operators offering separate travel packages and seeing demand surge in this segment:

- **EaseMyTrip:** Bookings linked to pets growing by 25-45 per cent each year
- **Thrillophilia:** Piloting curated 'pet-first' road trip packages
- **StayVista:** Saw increase of 30 per cent in bookings year-on-year
- **SaffronStays:** Bookings with pets soar by 80 per cent Y-o-Y in 2025

"The base is still small compared to our overall domestic leisure volume, but the growth rate is clearly higher than the rest of the portfolio. The sharpest spike is from millennial and Gen-Z pet parents in metros like Bengaluru, Mumbai, Delhi-NCR, Pune and Hyderabad who are choosing drivable getaways over long-haul flights so that their pets can travel with them," said Daga, adding that typically, the trip costs rises by 15 to 30 per cent with pets, depending on the season and destination.

With strong double-digit growth projected for this segment globally, Agarwal added that 'pawcation travel' has the potential to develop into a dedicated vertical, forming an integral part of experiential and personalised travel offerings.

In India, mostly hill stations such as Dharamshala, Rishikesh, Mussoorie, Manali, Coorg, Sikkim, Ooty and Himachal Pradesh attract travellers with pets, along with Lonavala, Goa, Jaipur and Puducherry. Internationally, destinations like Dubai, Thailand, Singapore, New York, Nice, Valencia, Rovinj, Toronto, Frankfurt, with several locations in Europe like Switzerland and Austria, attract Indian travellers with pets, according to travel operators.

While price and location remain key, pet policies have become a key factor influencing booking decisions among Indian travellers, with one out of five considering a property's pet-friendliness when choosing where to stay, Santosh Kumar, country manager for India, Sri Lanka, Maldives and Indonesia at Booking.com, noted. This growing demand for pet-friendly vacations is driving accommodations to enhance their offerings for travelling pet parents.

Corroborating with Kumar, Anil Kalsi, board member, Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality, said that accompanying pets is a new normal now, and some airlines and hotels have become pet-friendly in India. Hotels have sensed an opportunity as some have started providing pet care facilities for their guests, he added.

Apart from hotels, alternate accommodations like luxury villa rentals have also seen a rise in bookings for pet-friendly stays. Firms like StayVista and SaffronStays are enhancing their offering in this segment through partnerships with pet brands as well.

StayVista, which currently has 30 per cent of its portfolio in the pet-friendly category, saw an increase of 30 per cent in bookings year-on-year (Y-OY) for guests travelling with their pets. Its portfolio spans over 1,200 villas and more than 80 destinations in India.

"StayVista is actively expanding its pet-friendly inventory. By 2026, we aim to bring 50 per cent of our portfolio under the pet-friendly category, especially in drive-to destinations close to major metros," said Amit Damani, co-founder, StayVista.

Similarly, SaffronStays, a network of private luxury vacation homes, saw its bookings with pets soar by 80 per cent Y-o-Y in 2025. It currently has over 200 pet-friendly homes across India.

"Pet-inclusive travel is a meaningful and growing part of our long-term strategy," said Devendra Parulekar, founder, SaffronStays. "As more families choose private villas and estates for their holidays, pet-friendly homes naturally become a key differentiator. For us, this segment not only strengthens guest loyalty but also supports our vision of enabling families, in every sense of the word, to holiday together without compromise."

Dilip Buildcon Limited

(CIN: L45201MP2006PLC018689)
Regd. Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal (M.P)- 462016
Email Id : db@dilipbuildcon.co.in, **website :** www.dilipbuildcon.com
Tel. No. 0755-4029999, **Fax No.** 0755-4029998

NOTICE TO THE MEMBERS

The Members of Dilip Buildcon Limited ("the Company") are hereby informed that in compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Companies Act" or "the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standards – 2 (SS-2)on "General Meetings" issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, read with Circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), including the latest General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 (the "MCA Circulars") and Circulars issued from time to time by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (the "SEBI Circulars") (hereinafter collectively referred to as "the Applicable Laws"), the Company is seeking approval of its Members for passing of Resolutions by way of Postal Ballot as stated in the Postal Ballot Notice dated December 18, 2025 ("Postal Ballot Notice"). The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Thursday, December 18, 2025.

It may please be noted that the dispatch of Postal Ballot Notice to the Members has been made only through electronic mode to those Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository(ies) / Depository Participant(s), as on Friday, December 12, 2025 ("Cut-off Date") on their e-mail ids registered with the Company / Depositories / Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agent of the Company. The requirement of circulating the physical copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with, vide the MCA Circulars. However, it is clarified that all the persons who are Members of the Company as on Friday, December 12, 2025 (including those Members who may not have received this Notice due to non-registration of their e-mail IDs with the Company or with the Depositories / Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agent) will be entitled to vote in relation to the Resolution specified in the Notice and any person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purpose only.

In compliance with the provisions of the Applicable Laws, the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice, through e-voting services provided by MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) (MUFG).

Commencement of e-voting:	**9:00 a.m. (IST) on Friday, December 19, 2025**
End of e-voting:	**5:00 p.m. (IST) on Saturday, January 17, 2026**

The procedure / instructions for e-voting is / are given in the Postal Ballot Notice.

The copy of the said Postal Ballot Notice is being made available on the website of the Company, viz., www.dilipbuildcon.com and on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) (RTA) at www.in.mpms.mufg.com.

Please note that any Postal Ballot Form(s) / Electronic Votes received/casted from/by the Member(s) after the aforesaid time period, i.e., after 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, January 17, 2026**, will not be valid / allowed and will be strictly treated as if the reply from such Member(s) has not been received.

Members who have not registered their e-mail addresses with the Company or the Depositories are requested to do so by following the process mentioned in the Postal Ballot Notice dated December 18, 2025.

The results of voting on the Resolutions will be declared on or before January 20, 2026 and will be displayed at the website of the Company (www.dilipbuildcon.com), besides being communicated to the concerned Stock Exchanges.

For Dilip Buildcon Limited
Sd/-
Abhishek Shrivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Date: December 18, 2025
Place: Bhopal